

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का प्रतिबिंबन

सुनील कुमार उपाध्याय*

आज हम एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं, जहाँ एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमाम नए शैक्षिक सुधारों के साथ भारतीय विद्यार्थियों के लिए भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा का संकल्प व्यक्त करते हुए हमारे बीच उपस्थित है। जहाँ तक भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा की बात है, उसके स्वरूप को समझने के लिए महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन और उनकी शैक्षिक योजना के आलोक में इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। क्या यह शिक्षा नीति उसी तरह के भारत की कल्पना प्रस्तुत कर रही है, जैसा महात्मा गांधी भारत को देखना चाहते थे। क्या सर्वोदय व समग्र विकास की कोई अलग अवधारणा इसके मूल में है? कहीं समय के साथ कदमताल के प्रयास में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण को भारत पीछे तो नहीं छूटता जा रहा? और अगर महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं तो इस शिक्षा नीति में उनके शिक्षा संबंधी विचार किस तरह प्रतिबिंबित हो रहे हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ प्रस्तुत लेख में विमर्श को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक इस नीति के लक्ष्यों और आदर्शों की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस नीति ने भारत और भारत की समस्याओं को समझने और उसके समाधान के लिए महात्मा गांधी की दृष्टि को प्रासंगिक और महत्वपूर्ण माना है और उसे ही आधार मानकर भारत के भविष्य को देखने का प्रयास किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि क्रियान्वयन के स्तर पर शिथिलता न बरती गयी तो यह नीति निश्चित ही भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाली एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी।

शिक्षा किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। हालाँकि, यह हमारा सौभाग्य रहा है कि शिक्षा के मामले में भारत का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है, जहाँ सभ्यता के प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति एक अद्भुत प्रेम देखने को मिलता है। शिक्षा के प्रति अपने समर्पण की उदात्त परंपरा के लिए पहचाने जाने वाले वैदिक काल के गुरुकुलों से आज तक के अपने सफ़र में

शिक्षा व्यवस्था तमाम उतार-चढ़ावों की साक्षी भी रही है। वहीं आज हम पुनः एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं, जहाँ एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तमाम नए शैक्षिक परिवर्तनों व सुधारों की मुनादी कर रही है। यह शिक्षा नीति भारत के लोगों के लिए भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर केंद्रित शिक्षा की बात कर रही है। ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि क्या वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सुगम्यता की,

* एसोसिएट प्रोफ़ेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, डी.बी.एस. कॉलेज, कानपुर

समता की, गुणवत्ता की, वहनीयता की, जवाबदेही की हमारी लड़ाई को गति दे पाएगी? क्या यह सतत और समग्र विकास की लोक केंद्रित अवधारणा को एक सशक्त धरातल दे पाएगी?

शिक्षा के सम्मुख मैकालियन परिप्रेक्ष्य की चुनौती और महात्मा गांधी

जब भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है तो उसे समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम भारतीयता के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल रहे महात्मा गांधी हो सकते हैं। उनके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए भारतीय आदर्शों और आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा का स्वरूप क्या हो सकता है? महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधी संकल्पनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए 1835 में प्राच्य-पश्चात्य विवाद की पृष्ठभूमि में लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा से भिन्न पूरे राष्ट्र की शिक्षा परंपरा को ही बदलने के प्रयास को भी समझना होगा। बड़े ही कपटपूर्ण ढंग से लॉर्ड मैकाले ने 'सा विद्या या विमुक्तये' वाली शिक्षा को क्लर्क बनाने का साधन मात्र बना दिया। वह शिक्षा के माध्यम से पूरे भारतीय मानस को उसकी संस्कृति, उसकी जड़ों से काट देना चाह रहा था। वह कलकत्ता से अपने पिता को पत्र लिखता है कि, "...यदि हमारी शिक्षा योजना जारी रह गयी तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के संभ्रान्त वर्ग में कोई भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा" (ट्रेवेल्लान, 1889, पृष्ठ 330)। लेकिन भारत की विशेषता रही है कि भारत ने राजनैतिक आक्रमणों का भले सशक्त प्रतिकार न किया हो पर जब भी उस पर सांस्कृतिक आक्रमण होता है, तब भारत सशक्त

प्रतिकार करता है। लॉर्ड मैकाले की सांस्कृतिक विजय यात्रा को कलकत्ता के दक्षिण में ही एक सामान्य से दिखने वाले संत रामकृष्ण परमहंस ने ही रोक दिया। उस संत ने काली की एक मूर्ति के प्रति कलकत्ता या बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्था इतनी गहरी कर दी कि मैकाले की दम्भोक्ति ने कलकत्ता में ही दम तोड़ दिया। रामकृष्ण एक संत थे, उनकी भाषा बड़ी सहज और अनगढ़ थी, वे मूलतः अनुभूतियों के व्यक्ति थे (दिनकर, 1956)। लेकिन बाद में विवेकानन्द ने उनकी अनुभूतियों को बौद्धिक स्वरूप दिया, जिससे वे पश्चिमी बुद्धिवाद की चुनौती का सामना भी करते हैं और भारतीय गौरव की स्थापना भी।

हालाँकि, रामकृष्ण और विवेकानंद का कार्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में था। इन्होंने अपने व्यक्तित्व और वक्तव्य से भारतीयों में जो गौरव और आत्मविश्वास का संचार किया, उससे राजनीति के धरातल पर जब गांधी प्रकट होते हैं, तो भारतीयता के प्रतीक बन पूरे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे देते हैं। मैकाले को भी अगर किसी ने सीधी चुनौती दी तो वह गांधी ही थे। गांधी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कह देते थे कि मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी (गांधी, 1909, पृष्ठ 90)।

1927 में साइमन कमीशन के तहत शिक्षा संबंधी सुझाव हेतु ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। गोलमेज सम्मेलन में इसी समिति के सुझावों पर चर्चा हो रही थी। वहाँ गांधी ने यह आरोप लगाया कि ब्रिटिशर्स की उपस्थिति से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई है, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के रमणीय वृक्ष को नष्ट कर दिया है (धर्मपाल, 1983)।

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारत की बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शिक्षा के स्रोत को नष्ट कर दिया है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा की जो स्थिति है, उससे बेहतर तो अंग्रेजों के आने के पहले थी। इसके पूर्व 1911 में गोपल कृष्ण गोखले केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव ला चुके थे, जिसे वहाँ बहुत से भारतीयों का भी समर्थन नहीं मिला था। उनका मानना था कि इतने विशाल देश में सभी को शिक्षा दे पाना ब्रिटिश सरकार के लिए सम्भव नहीं है। महात्मा गांधी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन जैसे गैर परंपरागत तरीकों के अन्वेषक महात्मा गांधी एक अद्भुत शिक्षा योजना प्रस्तुत कर देते हैं, जो न केवल निःशुल्क है, बल्कि बेरोजगारी के खिलाफ बीमा करती हुई दिखती है।

महात्मा गांधी की शैक्षिक योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में शिक्षा-शास्त्रियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उनके शैक्षिक विचारों पर व्यापक विमर्श के उपरान्त एक शैक्षिक योजना को मूर्त रूप दिया गया। इस शैक्षिक योजना में वे 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उनके वातावरण से संबंधित किसी शिल्प के माध्यम से मातृभाषा में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की बात करते हैं। दुनिया के इतिहास की यह पहली ऐसी शिक्षा योजना है जो पूरी तरह स्वावलंबी है। श्रम को हेय दृष्टि से देखने के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था को बहुत गहरी चोट लगी थी। महात्मा गांधी श्रम की महत्ता स्थापित कर अपनी शिक्षा योजना से स्वावलंबन की भी बात करते हैं और एक समतावादी समाज की स्थापना को संकल्पित भी करते हुए दिखते

हैं। विद्यार्थी को उसके वातावरण से संबंधित किसी भी शिल्प की शिक्षा उसकी मातृभाषा में देकर न केवल विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाते हैं, बल्कि उसे उसकी संस्कृति से भी जोड़ते हैं। समता, श्रम की महत्ता, स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान, बुनियादी साक्षरता और कौशलों के माध्यम से स्वावलंबन ये सभी इस नयी शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांत हैं।

महात्मा गांधी, शिक्षा में बड़ा अभिनव प्रयोग करते हैं। वे यह समझ जाते हैं कि भारत की बदहाली का, गरीबी का, गुलामी का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजी शासन द्वारा लोगों से उनका व्यवसाय छीन लेना रहा है। मूलतः अंग्रेज भारत में यहाँ की आर्थिक समृद्धि से आकर्षित हो व्यापार के लिए आए थे। लेकिन यहाँ के शासक बनते ही उन्होंने यहाँ की तकनीकी कुशलता को नष्ट करना शुरू कर दिया और कच्चे माल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटिश नीतियों का परिणाम यह रहा कि भारत के कुटीर उद्योग एकदम समाप्त से हो गए। बेरोजगार आबादी मजबूरी में मजदूरी या छोटे मोटे कामों के लिए शहरों में आने लगी। अंग्रेजों की नीतियों से ही एक बड़ी आबादी गरीब और कमजोर हो रही थी। महात्मा गांधी इस पूरे दुष्चक्र को समझ रहे थे। उन्हें लग गया कि भारत की असली समस्या भारत के कुटीर उद्योगों की समाप्ति और लोगों की बेरोजगारी है। वे शिक्षा को ब्रिटिश दुष्चक्र और उससे उपजी गरीबी व बेरोजगारी से मुक्ति के माध्यम के रूप में चुन उसके उद्देश्यों के फलक को विस्तृत भी कर रहे थे और उसे राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के रूप में भी देख रहे थे। महात्मा गांधी ने इसलिए अपनी शिक्षा योजना में मृतप्राय हो चुके भारत के कुटीर उद्योगों को शिक्षा से जोड़कर उसे जीवनशक्ति देने का प्रयास किया और इसी माध्यम

से बेरोज़गारी से लड़ने का एक विकल्प भी प्रस्तुत किया। भारत में पहले व्यावसायिक शिक्षा गुरुकुलों से अलग परिवारों और जातियों में सीमित थी। महात्मा गांधी एक नया प्रयोग करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से एकीकृत कर देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी शिक्षा जो चित्त की शुद्धि न करे, निर्वाह का साधन न बनाये, स्वतंत्र रहने का सामर्थ्य न दे उस शिक्षा में चाहे जितना जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता व भाषा पाण्डित्य हो वह सच्ची शिक्षा नहीं। महात्मा गांधी विद्यार्थियों के वातावरण से संबंधित किसी शिल्प केंद्र में रखकर विद्यार्थियों को शिक्षा देने की योजना प्रस्तुत कर देते हैं।

आज यह प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस विषय में महत्वपूर्ण पहल हुई है। यह नीति स्थानीय परिवेश और उसकी आवश्यकताओं से जुड़े कौशलों से संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से अनुभव आधारित अधिगम की बात कर रही है। इसके लिए यह प्रत्येक विषय में इन क्रियाकलापों को एकीकृत करने हेतु कार्ययोजना बनाने की बात पर बल दे रही है। इस शिक्षा नीति में 2025 तक 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की गयी है। इसमें माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किए जाने की भी बात की गयी है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 10 दिन के बस्ता रहित कक्षा की बात की गयी है, जिसमें विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशलों के प्रशिक्षण देने की बात की गयी है। विद्यार्थियों में व्यावसायिक समझ बढ़ाने के लिए उन्हें अवकाश के दिनों में स्थानीय कौशलों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने की बात भी इस नीति में की गयी है। इससे विद्यार्थी मुख्यधारा की शिक्षा के साथ कौशल

विकास में भी संलग्न हो पाएँगे और प्रयास यह है कि वे कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीख लें। इससे उन्हें रोज़गार भी मिलेगा, श्रम की महत्ता भी स्थापित होगी और भारतीय कलाओं से वे जुड़कर उसको संरक्षित भी कर पाएँगे। पारंपरिक और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत कर व्यावसायिक शिक्षा के अनुक्रम और उस तक विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाने का प्रयास इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक समझ बल्कि चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशलों से विद्यार्थियों को सुसज्जित करना भी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् को यह ज़िम्मेदारी दी गयी है कि वे इससे संबंधित क्रियाकलापों को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की कार्ययोजना तैयार करें।

महात्मा गांधी अपनी शैक्षिक योजना में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कम से कम लिखने, पढ़ने और गणना के योग्य बना देना चाहते हैं। जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित किसी शिल्प को सीखते हुए उसी से संबंधित जानकारी को पढ़ना, लिखना और गणना करना, जो सीखने की पूरी प्रक्रिया को बोझिल होने से बचा लेता है। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति यह है कि असर (2018) के सर्वेक्षण बताते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी तक प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं दे पा रही है। अर्थात् ऐसे बच्चों में पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। नई शिक्षा नीति ने समस्या और उसके कारणों की पहचान कर साक्षरता और संख्या ज्ञान को मूलभूत कौशल मानते हुए रुचिकर

ढंग से और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाते हुए इस कौशल का ज्ञान कराने पर बल दिया है। इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना है और इसे सीखने की आवश्यक शर्त मान इसे एक राष्ट्रीय अभियान बनाने की ज़रूरत महसूस की गयी है। यह नीति बच्चे के विकास लिए आवश्यक मूलभूत कौशलों की प्राप्ति के लिए एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ने को संकल्पित दिख रही है, जो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों का ही वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप अनुकूलन है।

गांधी, ज्ञान को अनुशासनिक वर्गीकरण से बाहर खींच उसे समग्रता में लेते हुए, रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं। वे ज्ञान के विभिन्न पक्षों में आपस में संबंध स्थापित करते हुए बच्चे के वातावरण से संबंधित किसी शिल्प को केंद्र में रखकर समवाय (सहसंबंध) पद्धति द्वारा शिक्षा देने की बात करते हैं (पाण्डेय, 2017, पृ.133)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इन्हीं शैक्षिक आदर्शों व मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करने वाली समग्र शिक्षा पर बल दे रही।

यह नीति स्पष्ट रूप से अपने आधार सिद्धांत में कहती है कि विभिन्न अनुशासनों के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर क्रियाकलापों के बीच, व्यावसायिक और परंपरागत शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच की पारस्परिक दूरी और असंबद्धता को दूर किया जा सके। यह शिक्षा नीति फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज पर गतिविधि आधारित अध्ययन के प्रोत्साहन पर बल देती है, जिसके माध्यम से बच्चों में नैतिक गुणों स्वच्छता, सहयोग आदि आदतों का विकास

किया जाना है। इसके साथ ही विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से ही पढ़ने, लिखने, बोलने, कला, भाषा, विज्ञान, गणित, शारीरिक स्वास्थ्य जैसे विषयों की शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्टेज की तीन वर्ष की शिक्षा में विषयों का स्पष्ट विभाजन तो हो जाएगा और उनकी अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा लेकिन तब भी शिक्षा अनुभव आधारित होगी और विषयों के मध्य पारस्परिक संबंध देखने पर बल दिया जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को रटने की प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए संज्ञानात्मक समझ, चरित्र निर्माण और व्यावसायिक कुशलता की ओर ले जाना है।

इस नीति में बच्चों को विषयों में बाँधने से बचाने की महत्वपूर्ण पहल की गयी है। यह शिक्षा नीति बहु-विषयक और लचीली शिक्षा की बात कर रही है। इसमें बच्चे को अपनी पसंद के विषयों को पढ़ने की पूरी छूट है, जिससे बच्चे किसी वस्तु या घटना से संबंधित सभी पक्षों का ज्ञान अलग-अलग विषयों के माध्यम से प्राप्त कर ज्ञान उस, वस्तु या घटना की व्यापक समझ विकसित कर सकते हैं। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महात्मा गांधी का एक स्पष्ट और विराट प्रतिबिंबन दिख रहा है।

यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों को स्थानीय संदर्भों से जोड़ने के प्रयास करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्यों, आदर्शों, साहित्य, कला, संस्कृति के प्रति खुले रूप में अपना लगाव दिखा रही है और विद्यार्थियों को इससे जोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कर रही है। यह शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण पहल करते हुए सीखने में मातृभाषा के महत्व को केवल स्वीकार ही नहीं कर रही बल्कि उसकी पुरजोर वकालत भी कर रही। यह नीति इस बात पर जोर दे रही है कि बच्चे के बौद्धिक व सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए

मातृभाषा में शिक्षा आवश्यक है। साथ ही अंग्रेजी भाषा के समर्थन में दिए जा रहे तर्कों का उत्तर देते यह भी कह रही कि दूसरी भाषा को सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उस भाषा को शिक्षा का माध्यम ही बनाया जाए। उसे एक विषय के रूप में अध्ययन कर भी सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो वह जिस दौर में अपनी शिक्षा योजना लेकर आए थे, वह दौर ही अंग्रेजी का था। शिक्षा का पर्याय ही अंग्रेजी शिक्षा थी। लेकिन महात्मा गांधी जिस तरह से भारत की आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का कारण कुटीर उद्योगों की समाप्ति मानते हैं, ठीक उसी तरह अपनी भाषाओं की उपेक्षा व उससे अलगाव को भी तमाम सांस्कृतिक, राजनीतिक व शैक्षिक समस्याओं का कारण मानते हैं।

कोई भी भाषा अपने समाज की संस्कृति की वाहक होती है। विलियम जोन्स ने जिस संस्कृत को ग्रीक से अधिक परिपूर्ण और लैटिन से अधिक समृद्ध और इन दोनों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और मनोहारी माना। जिस संस्कृत में ज्ञान का विपुल भण्डार है, जो भाषा आज भी सर्वाधिक वैज्ञानिक मानी जाती है व कम्प्यूटर तक के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी गयी, उसे भी उपेक्षित किया जाना भारतीयों द्वारा खुद के साथ किया गया एक बड़ा अपराध है। यह शिक्षा नीति संस्कृत के संरक्षण के प्रयासों पर बल देने की बात कर रही है, जो भारतीय ज्ञान के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

हम वैज्ञानिक अनुसंधानों में दुनिया के देशों से पिछड़ रहे, इसका एक कारण यह भी है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान से न अपने को जोड़ पा रहे हैं और न ही उससे प्रेरणा ले पा रहे हैं, क्योंकि इसमें भाषा एक अवरोधक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। वहीं

दूसरी तरफ अपनी मातृभाषा में शिक्षा न लेना भी हमारी बौद्धिक विफलताओं का कारण है। दुनिया के तमाम मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देना विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। मातृभाषा में हम विषयवस्तु को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यही कारण भी है कि दुनिया के अधिकांश विकसित देश मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। भारत में भाषाओं की एक समृद्ध परंपरा और सुदृढ़ नींव है, फिर भी अपनी भाषा से विमुख हो अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी संस्कृति की कीमत पर अपनी शिक्षा जारी रखे हुए हैं। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शास्त्रीय और मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में लाने का प्रयास कर पूरी शैक्षिक संरचना को ही नया कलेवर देने का प्रयास किया है। यदि इसे वास्तविक धरातल पर अमल कर दिया गया तो निश्चित ही भारत में शिक्षा और उसके माध्यम से नवीन ज्ञान के विकास हेतु अनुसंधानों के स्तर में बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा।

वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा, कला, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, भाषा, प्राचीन वाङ्मय, शिल्प और इन सभी को शिक्षा से जोड़कर व उनके संरक्षण, संवर्धन और आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरण की बात करती है। वस्तुतः यह शिक्षा नीति भारतीय समस्याओं की जड़ों को खोजती व उनका समाधान भारतीय संदर्भों के साथ करने का प्रयास कर रही है, और ऐसी ही महात्मा गांधी की भी भावना थी।

निष्कर्ष

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को समेटे हुए है। चाहे शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की बात हो या मातृभाषा में शिक्षा प्रदान

करने की हो या फिर बच्चों में मूलभूत कौशलों के विकास की बात हो, इन सभी विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर महात्मा गांधी का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का भी सर्वाधिक ज़ोर इन्हीं बातों पर था। समता, श्रम की महत्ता, स्थानीय परिवेश से जुड़ाव, ज्ञान की अखंडता, बुनियादी साक्षरता और स्वावलंबन— ये सभी इस नई शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांत हैं। इस शिक्षा नीति में इन निर्धारित आदर्शों को प्राप्त करने हेतु विषयगत, प्रक्रियागत और संरचनागत बदलावों और शैक्षिक विसंगतियों, समस्याओं के साथ जूझने का

संकल्प दिख रहा है। निश्चित ही यह शिक्षा नीति भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाली एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगी। आशा की जा सकती है कि जिस तरह इस दस्तावेज के माध्यम से भारत की शैक्षिक समस्याओं की जड़ में जाने व उसका समाधान खोजने का प्रयास किया गया है, उसी तरह से इस नीति के क्रियान्वयन के स्तर पर भी गंभीरता दिखायी जाएगी। शिक्षा से जुड़े लोगों की इसके क्रियान्वयन के प्रति दृढ़ संकल्प शक्ति बनी रही तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निश्चित ही भारतीय शिक्षा को नई दिशा देगी।

संदर्भ

- असर. 2018. *एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट*. असर सेन्टर, नयी दिल्ली.
- गांधी, मोहन दास करमचंद. 1909. *हिन्द स्वराज्य*. (अनुवादक- अमृतलाल ठाकोरदास नाणावटी). सर्वसेवा संघ, वाराणसी.
- ट्रेवेल्स, जी. ओ. 1889. *द लाइफ एण्ड लेटर्स ऑफ़ लार्ड मैकॉले*. लॉगमन्स, ग्रीन एण्ड कंपनी, लंदन.
- धर्मपाल. 1983. *द ब्यूटीफुल ट्री*. बिब्लिआ इम्पेक्स प्रा. लि., नयी दिल्ली.
- दिनकर, रामधारी सिंह. 1956. *संस्कृति के चार अध्याय*. लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद.
- पाण्डेय, राम शकल. 2017. *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास*. श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.